भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 400

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

400. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) विक्रेताओं के लिए ग्राहक जोड़ने और लेनदेन करने की लागत को कम करेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओएनडीसी के तहत विभिन्न प्लेटफॉर्मो को आपस में जोड़ने की व्यवस्था करके बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओएनडीसी के जरिए छोटे व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और स्थानीय कारीगरों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) ओएनडीसी देश में डिजिटल वाणिज्य के क्षेत्रीय और भाषाई अंतर को किस प्रकार दूर करने की योजना बना रहा है; और

(ङ) खरीदारों को अधिक विकल्प और ज्यादा विक्रेताओं तक पहुंच देने के लिए ओएनडीसी किस प्रकार काम करेगा?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), धारा 8 की कंपनी है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी विकेन्द्रीकृत और अंतर-संचालनीय नेटवर्क को सक्षम बना कर विक्रेताओं

के लिए ग्राहक जोड़ने और लेनदेन की प्रक्रिया की लागत को कम करता है। ओएनडीसी कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या मार्केटप्लेस नहीं है, बल्कि एक ओपन प्रोटोकॉल है जिस पर प्लेटफॉर्म/मार्केटप्लेस बनाया जा सकता है।

परम्परागत ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से भिन्न, ओएनडीसी किसी एक कंपनी पर निर्भरता को कम करके विभिन्न प्लेटफार्मों पर क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को बढ़ावा देता है।

किसी भी ओएनडीसी-कम्प्लायंट विक्रेता एप्लिकेशन के माध्यम से शामिल किया गया विक्रेता, सभी ओएनडीसी-कम्प्लायंट क्रेता एप्लिकेशन के लिए तलाश करने योग्य हो जाता है, जिससे बाजार में पहुंच बढ़ती है और ग्राहक जोड़ने की लागत कम होती है। ओएनडीसी निम्निलखित दो प्रमुख तंत्रों के माध्यम से ग्राहक जोड़ने की लागत कम करता है:

i. **ग्राहक पूल में वृद्धि** - ओएनडीसी डिजिटल रूप से अपेक्षाकृत कम सेवा प्राप्त और इस सेवा के दायरे से बाहर के उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स ईकोसिस्टम में लाता है, जिससे विक्रेताओं की पहुंच का विस्तार होता है।
ii. **मौजूदा ग्राहक पूल के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना** - ओएनडीसी फिनटेक, मोबिलिटी और अन्य ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत होता है, जिनके पास पहले से ही संस्थापित उपयोगकर्ता बेस मौजूद होता है, जिससे विक्रेताओं को व्यापक ग्राहकों तक पहुंच में मदद मिलती है।

इसके अलावा, विक्रेता एप्लिकेशनों में प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि परम्परागत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा लगाए जाने वाले अधिक कमीशन शुल्क की तुलना में लेनदेन शुल्क प्रतिस्पर्धी बना रहे।

वास्तविक मार्जिन नेटवर्क प्रतिभागियों और उनकी वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर अलग-अलग होता है।

(ख): ओएनडीसी को एक ओपन नेटवर्क के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित हुए बिना लेन-देन कर सकता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **अंतर-संचालनीयता:** ओएनडीसी नेटवर्क के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शामिल विक्रेताओं को किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर क्रेता द्वारा खोजा जा सकता है,

जिससे कुछ ही बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व बने रहने की स्थिति में कमी आती है।

ii. **अनबंडलिंग:** परम्परागत ई-कॉमर्स मॉडल के विपरीत, ओएनडीसी विभिन्न कंपनियों को वाणिज्य की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक साथ लाने की चिंता किए बिना अपने विशिष्ट पहल की विशेषज्ञता हासिल करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक प्रतिस्पर्धी और विविधतापूर्ण बाजार सुनिश्चित करता है।

iii. **बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा:** ओएनडीसी की विकेन्द्रीकृत प्रकृति प्लेटफार्मों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, कमीशन को कम करती है तथा छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए डिजिटल कॉमर्स को अधिक व्यवहार्य बनाती है।

(ग): केंद्र और राज्य स्तर पर कई मंत्रालय छोटे व्यवसायों, खुदरा विक्रेताओं, कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए ओएनडीसी को अपनाने पर बल दे रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में उठाए गए उल्लेखनीय कदम निम्नानुसार हैं:-

केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहलें:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने व्यापार सक्षमता और विपणन (टीईएएम) स्कीम शुरू की है, जो ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, लेखा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ओएनडीसी में शामिल करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। उल्लेखनीय है कि इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लाभार्थियों में से आधे महिला-स्वामित्व वाले उद्यम होंगे।

ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म eSaras.in, ओएनडीसी पर लाइव है - जिसका संचालन दिल्ली-एनसीआर में स्थित एक केंद्रीय वेयरहाउस से होता है। ई-सरस (e-Saras) ओएनडीसी के साथ एकीकृत है और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए लगभग 800 से अधिक हस्तकला उत्पाद अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलें:

i. हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचपी एसआरएलएम) के अंतर्गत *हिमलरा* ब्रांड के माध्यम से, स्थानीय और

स्वदेशी उत्पादों को ओएनडीसी में शामिल करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

ii. आंध्र प्रदेश: स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों सहित छोटे व्यवसायों को ओएनडीसी के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, ओएनडीसी ने स्थानीय व्यवसायों और छोटे विक्रेताओं को शामिल करने और उनकी सहायता के लिए कई उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. स्थानीय व्यवसायों और छोटे विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स तक पहुंच और उसके लाभ पहुंचाने हेतु समाधान तैयार करने के लिए स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों के बड़े नेटवर्क की सहायता करना।

ii. छोटे व्यवसायों और स्थानीय विक्रेताओं के लिए डिजिटल कॉमर्स से जुड़ने और उसका लाभ उठाने हेतु प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विकास, सहायता और प्रचार-प्रसार करना, जिसमें ओएनडीसी पर 3000 से अधिक घंटों का वर्चुअल प्रशिक्षण और ओपन डिजिटल सत्रों के माध्यम से 200 से अधिक घंटों का तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। इसमें 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स, छात्र, व्यावसायिक उद्यमी आदि शामिल हुए।

iii. ओएनडीसी ने विक्रेताओं (विशेषकर पहली बार के विक्रेताओं) को डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में सफल होने में मदद करने के लिए 14 भाषाओं में एक हैंडबुक तैयार की है और इसे व्यापक रूप से संवितरित किया जा रहा है।

iv. ओएनडीसी विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक क्षेत्र के विक्रेताओं और सूक्ष्म उद्यमियों को सिडबी, नाबार्ड और अन्य लोकोपकारी एवं विकास संगठनों जैसे ईकोसिस्टम भागीदारों की सहायता से ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

v. भारत के गांवों को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ओएनडीसी पर लाइव हो गए हैं।

(घ): ओएनडीसी ने पूरे भारत में डिजिटल कॉमर्स की पहुंच का विस्तार कर दिया है। डिजिटल कॉमर्स की पहुंच और अधिक बढ़ाने के लिए ओएनडीसी द्वारा किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:

i. ओएनडीसी ने विक्रेताओं (विशेषकर पहली बार के विक्रेताओं) को डिजिटल कॉमर्स में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए 14 भाषाओं में एक

बहुभाषी विक्रेता पुस्तिका तैयार की है और इसे व्यापक रूप से संवितरित किया जा रहा है।

ii. ओएनडीसी ने भारतीय भाषाओं में ऐप के विकास और ई-कॉमर्स को बेहतर बनाने के लिए भाषिणी के साथ साझेदारी की है।

iii. ओएनडीसी सहायक - व्हाट्सएप बॉट "ओएनडीसी सहायक" 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिसका 22 भाषाओं तक विस्तार किया जाना है, ताकि विक्रेताओं और क्रेताओं को ओएनडीसी के बारे में जानकारी मिल सके।

iv. ओएनडीसी-सक्षम क्रेता और विक्रेता एप्लीकेशनों को विविध उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय भाषाओं में इंटरफेस प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

v. विभिन्न डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को भाग लेने की अनुमति देकर, ओएनडीसी क्षेत्रीय व्यवसायों को भाषा संबंधी बाधाओं के बिना ग्राहकों से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

(ङ): ओएनडीसी निम्नलिखित विधियों से क्रेताओं के लिए विकल्प बढ़ाता है:-

i. **विक्रेता आधार का व्यापक विस्तार:** कोई भी विक्रेता, चाहे वह किसी भी प्लेटफॉर्म या स्थान पर हो, क्रेताओं द्वारा कई ओएनडीसी- कम्प्लायंट क्रेता एप्लीकेशन के माध्यम से खोजा जा सकता है।

ii. **विविध उत्पाद उपलब्ध कराना:** ओएनडीसी पहली बार के विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स के दायरे में शामिल करता है, जिससे छोटे व्यवसायों, स्थानीय कारीगरों और क्षेत्रीय ब्रांडों को बड़े उद्यमों के साथ दृश्यता की सुविधा मिलती है, जिससे उपलब्ध उत्पादों के रेंज का विस्तार होता है।

iii. **प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण:** विक्रेता की बढ़ी हुई भागीदारी सही मूल्य निर्धारण की ओर ले जाती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, और उपभोक्ताओं के लिए लागत संबंधी लाभ सुनिश्चित करती है।

iv. **हाइपरलोकल मार्केट एक्सेस:** ओएनडीसी स्थानीय व्यवसायों और विशिष्ट बाजारों को डिजिटल खरीदारों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे क्षेत्र-विशिष्ट और विशिष्ट उत्पादों की उपलब्धता बढ़ जाती है।

****